

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 161]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 मार्च 2014—चैत्र 7, शक 1936

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2014

क्र. एफ 1-33-2013-बावन-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश हाथकरघा संचालनालय (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1986 को प्रतिस्थापित करते हुए, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश हाथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय (राजपत्रित) सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश हाथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2014 है.

(2) ये “मध्यप्रदेश राजपत्र” में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे;

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ख) “आयोग” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

(ग) “समिति” से अभिप्रेत है, चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति;

(घ) “आयुक्त” से अभिप्रेत है, आयुक्त हाथकरघा एवं हस्तशिल्प;

(ङ) “परीक्षा” से अभिप्रेत है, नियम 12 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए आयोजित की गई प्रतियोगिता परीक्षा;

- (च) “सरकार” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (छ) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
- (झ) “अन्य पिछड़ा वर्ग” से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा, समय-समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना क्र. एफ 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ज) “अनुसूची” से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (ञ) “अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (ट) “अनुसूचित जनजाति” से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (ठ) “सेवा” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश हाथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय विभाग (राजपत्रित) सेवा;
- (ड) “राज्य” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

3. विस्तार तथा लागू होना.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम अनुसूची-एक में यथाउल्लिखित सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. सेवा का गठन.—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

- (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप में धारण कर रहे हों;
- (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और
- (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों.

5. सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान आदि.—(1) सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी :

परन्तु सरकार, समय-समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

(2) सेवा के सदस्य वित्त विभाग द्वारा जारी के परिपत्र क्र. एफ-11-1-2008-नियम-4, दिनांक 24 फरवरी 2008 के उपबंधों के अधीन समयमान वेतनमान के हकदार होंगे.

6. भर्ती का तरीका.—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा/चयन या साक्षात्कार या दोनों द्वारा;
- (ख) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) उन व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल रूप में या स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हैं जैसा कि सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए,

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट किए गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, यदि अपेक्षित हो, आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो तो वह सामान्य प्रशासन विभाग तथा आयोग की पूर्व सहमति के पश्चात् उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी, जो वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करे.

7. सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, सरकार द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.—परीक्षा में चयन के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

आयु.—(क) उसने परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी के लिए उच्चतम आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, आयु सीमा उस सीमा तक तथा नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :

(एक) कोई अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) कोई अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) कोई अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं हो;

स्पष्टीकरण.—शब्द छंटनी किए गए शासकीय कर्मचारी से द्योतक है, ऐसे व्यक्ति जो इस राज्य अथवा किसी भी संघटक इकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में छह माह तक निरन्तर रहा हो और वह रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो.

- (चार) कोई अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक है उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा है और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई थी या जो अधिशेष घोषित किया गया हो :—

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें सेवानिवृत्ति (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो और जिसे:—
 - (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;
 - (ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण कर लेने पर;
 सेवोन्मुक्त किया गया हो.
- (3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के ऐसे भूतपूर्व सैनिक.
- (4) संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किए गए ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं.
- (5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया है.
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया है.
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं रहे.
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो.
- (घ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 में यथाउपबंधित महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ङ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पति के पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (च) विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

- (छ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन "ग्रीनकार्ड" धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ज) "विक्रम पुरस्कार" प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जो, मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नान-कमीशनड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 3 वर्ष की सीमा के अध्वधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं हो;
- (ट) निराश्रित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी;

टिप्पणी .—(1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपर्युक्त नियम 8 (1) (ग) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन के लिए सम्मिलित किया गया हो, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा/चयन के या तो पूर्व में अथवा उसके पश्चात् सेवा से त्याग-पत्र दे देते हैं तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि, यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी की जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे. किसी अन्य मामले में उनकी आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी.

- (2) विभागीय अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन में प्रवेश के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी.
- (3) सभी प्रकार की छूट को आयु में सम्मिलित करते हुए किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी. अधिकतम आयु सीमा का आधार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 3-11-12-1-3, दिनांक 3 नवम्बर 2012 एवं 20 नवम्बर 2012 होगा.
- (2) **शैक्षणिक अर्हताएं.**—अभ्यर्थी के पास, अनुसूची-तीन में विनिर्दिष्ट सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए :

परन्तु :—

- (क) आयोग, अपवादिक मामलों में, सरकार के परामर्श से, उसकी सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जिसके पास यद्यपि इन खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो आयोग अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन में प्रवेश के लिए पात्र ठहराता हो;
- (ख) ऐसे अभ्यर्थी जो अन्यथा अर्ह हैं, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधि प्राप्त की हो जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता नहीं दी है, उन पर भी आयोग के विवेकानुसार चयन में उपस्थित होने के लिए विचार किया जा सकेगा.
- (3) **फीस.**— अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

9. निरर्हता.—(1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा परीक्षा/चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जा सकेगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी, सेवा में नियुक्ति/पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो।

(3) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हैं, तो उसकी नियुक्ति, आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखी जायेगी।

(5) पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं और महिला अभ्यर्थी के मामले में, जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया है, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।

10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.—चयन में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

11. प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भरती.—(1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा तथा साक्षात्कार ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जैसा कि सरकार, आयोग के परामर्श से, समय-समय पर अवधारित करे;

(2) आयोग द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जाएगी, जो कि सरकार, आयोग के परामर्श से समय-समय पर जारी करे।

(3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार सीधी भरती के प्रक्रम पर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्त पदों को भरते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों की नियुक्ति उसी क्रम में की जाएगी जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट चयन सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को, जिन्हें समिति द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया जाए, यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निःशक्त अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित होंगे. आरक्षण सम स्तर (Horizontal) और प्रभागवार (Comportmentwise) रहेगा.

(7) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(8) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों सकें तो शेष रिक्तियां सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरी जायेंगी और ऐसी रिक्तियां आगामी चयन के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी.

(9) अभ्यर्थी को अपनी पूरी सेवा कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उपबन्धों का पालन करना होगा.

12. आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.—(1) आयोग उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची तैयार करेगा और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा जो ऐसे स्तर से अर्ह हों जैसा कि आयोग अवधारित करें तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं, फिर भी जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है. योग्यता के क्रम में तैयार करेगा और सरकार को अग्रेषित करेगा. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी.

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अधधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक सरकार का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(4) आयोग द्वारा चयन सूची जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक विधिमाम्य रहेगी जो आयोग की सहमति से छह माह की कालावधि के लिए बढ़ाई जाएगी.

13. परिवीक्षा.—सेवा में सीधी भरती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

14. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.—(1) पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु एक समिति गठित की जाएगी जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य होंगे :

परंतु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर, नामनिर्देशित किए गए सदस्यों में से कोई अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो उसी प्रास्थिति का अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों प्रवर्ग का एक सदस्य पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जाएगा और विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जायेगी.

(2) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक साधारणतयः वर्ष में कम से कम एक बार होगी.

(3) **नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन**—नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाण का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम और नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी किये गये अनुदेशों तथा बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति की प्रक्रिया शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार होगी।

15. पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.—(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिसने उस वर्ष की पहली जनवरी को, उस पद पर, जिससे पदोन्नति की जानी है, या जिसने सरकार द्वारा उनके समतुल्य घोषित किए गए किसी अन्य पद पर उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) पूर्ण कर ली हो, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में हों :

परन्तु किसी कनिष्ठ व्यक्ति को वरिष्ठ व्यक्ति पर केवल इस तथ्य पर अधिमान नहीं दिया जाएगा कि उसने इस उपनियम में उल्लिखित विहित सेवा पूर्ण कर ली है।

(2) अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए विचारण क्षेत्र हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंध लागू होंगे।

16. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.—(1) समिति ऐसे समुचित व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम, 15 में अधिकथित शर्तें पूरी करते हों और जो पदोन्नति के लिए पात्र हों। यह सूची, चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(2) चयन सूची तैयार करने के लिए मापदण्ड, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार होगा।

(3) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची-चार के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे :

स्पष्टीकरण—कोई व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों पर, जिनका पश्चात्पूर्वी चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा।

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान सेवा के किसी सदस्य को अधिक्रमित करना प्रस्तावित किया जाता हो तो समिति, प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को अभिलिखित करेगी।

17. आयोग से परामर्श.—विभागीय पदोन्नति समिति की, जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या सदस्य द्वारा की गई हो, सिफारिश के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के अधीन आयोग से परामर्श की अपेक्षा के अनुपालन में की गई है तथा आयोग से पृथक् से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

18. **चयन सूची.**—(1) सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची-चार के कालम (2) में दशाए गये पदों से अनुसूची-चार के कालम (3) में वर्णित किए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(2) चयन सूची, सामान्यतः जब तक प्रवृत्त में रहेगी जब तक कि नियम-16 के उपबंधों के अनुसार या तो उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसके तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की पद पर रहते हुए आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में कोई गंभीर चूक होने की दशा में, सरकार की प्रेरणा पर चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और आयोग, यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगा.

19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**—(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा में संवर्ग (केडर) के पदों पर नियुक्ति उसी वरिष्ठता के क्रम से की जाएगी, जिस क्रम में ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में आए हों.

(2) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हैं, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने और उसकी प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी गिरावट न आई हो जिससे की वह सरकार की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त हो गया हो.

20. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

21. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला, ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उस व्यक्ति के लिए कम अनुकूल हो.

22. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में, की कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा, इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

23. **निरसन.**—मध्यप्रदेश हाथकरघा संचालनालय (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1986 तथा इन नियमों के तत्स्थानी नियम यदि कोई हो, और जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हो, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है.

अनुसूची—एक

(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अतिरिक्त संचालक, ग्रामोद्योग	1	मध्यप्रदेश हाथकरघा संचालनालय (राजपत्रित) सेवा प्रथम श्रेणी.	रुपये—37400—67000+8700
2	संयुक्त संचालक, ग्रामोद्योग (हाथकरघा)	1	—तदैव—	रुपये—15600—39100+7600
3	संयुक्त संचालक, ग्रामोद्योग (तकनीकी)	1	—तदैव—	रुपये—15600—39100+7600
4	उप संचालक, ग्रामोद्योग (हाथकरघा)	5	—तदैव—	रुपये—15600—39100+6600
5	उप संचालक, ग्रामोद्योग (तकनीकी)	5	—तदैव—	रुपये—15600—39100+6600
6	उप संचालक, (वित्त)	1	—तदैव—	रुपये—15600—39100+6600
7	सहायक संचालक, ग्रामोद्योग (हाथकरघा)	29	मध्यप्रदेश हाथकरघा संचालनालय (राजपत्रित) सेवा द्वितीय श्रेणी.	रुपये—15600—39100+5400
8	सहायक संचालक, ग्रामोद्योग (तकनीकी)	25	—तदैव—	रुपये—15600—39100+5400
9	वरिष्ठ निज सहायक	2	—तदैव—	रुपये—9300—34800+4200

अनुसूची—दो
(नियम 6 देखिए)

भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा/पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा [नियम 6(1)(ग) देखिये]	अभियुक्तियां
(1)	(2)	(3)	सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6(1)(क) देखिये]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1)(ख) देखिये]	(6)	(7)
हाथकरघा संचालनालय.	मध्यप्रदेश हाथकरघा संचालनालय (राजपत्रित) सेवा.					
	अतिरिक्त संचालक, ग्रामोद्योग.	1	-	100 प्रतिशत	-	-
	संयुक्त संचालक, ग्रामोद्योग (हाथकरघा).	1	-	100 प्रतिशत	-	-
	संयुक्त संचालक, ग्रामोद्योग (तकनीकी).	1	-	100 प्रतिशत	-	-
	उप संचालक, ग्रामोद्योग (हाथकरघा).	5	-	100 प्रतिशत	-	-
	उप संचालक, ग्रामोद्योग (तकनीकी).	5	-	100 प्रतिशत	-	-
	उप संचालक, (वित्त).	1	-	-	100 प्रतिशत	लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर.
	सहायक संचालक, ग्रामोद्योग (हाथकरघा).	29	40 प्रतिशत	60 प्रतिशत	-	पदोन्नति के लिए कुल पदों में से एक पद की पूर्ति लिपिकवर्गीय संवर्ग (अधीक्षक) से एवं एक पद की पूर्ति स्टेनो संवर्ग (वरिष्ठ निज सहायक) से पदोन्नति द्वारा की जाएगी.
	सहायक संचालक, ग्रामोद्योग (तकनीकी).	25	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-	-
	वरिष्ठ निज सहायक	2	-	100 प्रतिशत	-	-

अनुसूची—तीन

(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम आयु तथा अर्हता

विभाग का नाम	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

हाथकरघा मध्यप्रदेश हाथकरघा संचालनालय
संचालनालय. (राजपत्रित) सेवा द्वितीय श्रेणी.

सहायक संचालक, ग्रामोद्योग
(हाथकरघा).

21 वर्ष

40 वर्ष

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला/विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक उपाधि.
2. हाथकरघा एवं अन्य लघु उद्योगों एवं सहकारिता से संबंधित कार्य का दो वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जाएगी.

सहायक संचालक,
ग्रामोद्योग (तकनीकी).

21 वर्ष

40 वर्ष

1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से टेक्सटाईल / विविंग / हैण्डलूम टेक्नोलाजी में तीन वर्ष का डिप्लोमा / डिग्री.
2. टेक्सटाईल / उद्योग में कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा.
3. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.

अनुसूची—चार
(नियम 13 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति की पात्रता होने के लिए निम्न पद पर कार्य के अनुभव की कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
हाथकरघा संचालनालय.	मध्यप्रदेश हाथकरघा संचालनालय (राजपत्रित) सेवा. संयुक्त संचालक, ग्रामोद्योग (हाथकरघा) संयुक्त संचालक, ग्रामोद्योग (तकनीकी).	अतिरिक्त संचालक, ग्रामोद्योग.	5 वर्ष	1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य—अध्यक्ष. 2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव मध्यप्रदेश शासन कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग—सदस्य. 3. आयुक्त/संचालक, हाथकरघा संचालनालय—सदस्य. 4. समान रैंक के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का नामनिर्दिष्ट—सदस्य.
	उप संचालक, ग्रामोद्योग (हाथकरघा).	संयुक्त संचालक, ग्रामोद्योग (हाथकरघा).	5 वर्ष	— ” —
	उप संचालक, ग्रामोद्योग (तकनीकी).	संयुक्त संचालक, ग्रामोद्योग (तकनीकी).	5 वर्ष	— ” —
	सहायक संचालक, ग्रामोद्योग (हाथकरघा).	उप संचालक, ग्रामोद्योग (हाथकरघा).	5 वर्ष	— ” —
	सहायक संचालक, ग्रामोद्योग (तकनीकी).	उप संचालक, ग्रामोद्योग (तकनीकी).	5 वर्ष	— ” —
	ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (हाथकरघा).	सहायक संचालक, ग्रामोद्योग (हाथकरघा).	5 वर्ष	— ” —
	ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (तकनीकी).	सहायक संचालक, ग्रामोद्योग (तकनीकी).	5 वर्ष	— ” —
	अधीक्षक	सहायक संचालक, ग्रामोद्योग (हाथकरघा).	5 वर्ष	— ” —
	वरिष्ठ निज सहायक	सहायक संचालक, ग्रामोद्योग (हाथकरघा).	5 वर्ष	— ” —

No.F. 1-33-2013-LII-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, Madhya Pradesh Directorate of Handlooms (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1986 has been substituted by the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules related to the recruitment and service conditions of the members of the Madhya Pradesh Directorate of Handloom and Handicraft (Gazetted) Service, namely:—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Directorate of Handloom and Handicraft (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “**Appointing Authority**” in respect of the service means the Government of Madhya Pradesh;
- (b) “**Commission**” means the Madhya Pradesh Public Service Commission;
- (c) “**Committee**” means the Selection Committee / Departmental Promotion Committee;
- (d) “**Commissioner**” means the Commissioner of Handloom and Handicraft;
- (e) “**Examination**” means a competitive examination for recruitment to the service held under rules 12;
- (f) “**Government**” means the Government of Madhya Pradesh;
- (g) “**Governor**” means the Governor of Madhya Pradesh;
- (h) “**Other Backward Classes**” means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government *vide* Notification No. F 85/XXV/4/84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time;
- (i) “**Schedules**” means schedules appended to these rules;
- (j) “**Scheduled Castes**” means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or community specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;
- (k) “**Scheduled Tribes**” means any tribe, tribal community or part of or group within a tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;
- (l) “**Service**” means the Madhya Pradesh Directorate of Handloom and Handicraft Department (Gazetted) Service;
- (m) “**State**” means the State of Madhya Pradesh.

3. **Scope and application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every members of the Service as mentioned in Schedule I.

4. **Constitution of the Service.**—The service shall consist of the following persons, namely :—

- (1) The persons who at the time of commencement of these rules are holding substantively or in the officiating capacity the posts specified in Schedule-I;
- (2) The persons recruited to the service before the commencement of these rules; and
- (3) The persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification of Service, Scale of Pay, etc.—(1) The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provision contained in Schedule-I :

Provided that the Government may from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

(2) Members of the service shall be entitled to Time-Scale of pay under the provisions of the Circular No. F-11-1-2008-Niyam-4 dated 24-02-2008 issued by the Finance Department.

6. Method of recruitment.—(1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by one of the following methods, namely:—

- (a) by direct recruitment through Competitive Examination/Selection or interview are by both;
- (b) by promotion of the members of the service, as specified in column (2) of Schedule IV;
- (c) by transfer of persons who holds in a substantive or in officiating capacity, such posts in such services as may be specified in this behalf by the Government.

(2) The number of persons recruited, under clause (b) or clause (c) of sub-rule(1) shall not at any time exceed the percentage specified in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission, if required.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, it may after prior concurrence of the General Administration Department and the Commission adopt such methods of recruitment to the service, other than those specified in the said sub-rule, as it may by order issued in this behalf, prescribe.

7. Appointment to the service.—All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitment.—In order to be eligible for selection for examination a candidate must satisfy the following conditions, namely:—

- (1) **Age.—**(a) he must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and have not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination / selection;
- (b) the upper age limit shall be relaxed up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Castes or a Scheduled Tribes and Other Backward Classes;
- (c) the age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below :—
 - (i) A candidate who is a permanent Government Servant should not be more than 45 years of age.
 - (ii) A candidate who is holding a temporary post and applying for any other post should not be more than 45 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committees.

- (iii) A candidate, who is a retrenched Government Servant, shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years, even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation .—The term retrenched Government servant denotes a person who was in temporary Government Services of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of six months and who was discharged because of reduction in establishment, not more than three years period to the date of his registration at employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

- (iv) A candidate, who is an ex-serviceman, shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation .—The term “ex-servicemen” denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India, for a continuous period of not less than six months, and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service:—

- (1) Ex-servicemen released under mustering out concessions.
- (2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on
 - (a) Completion of short term engagement;
 - (b) Fulfilling the conditions of enrollment;
- (3) Such ex-personnel from Madras Civil Unit.
- (4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including short service regular commissioned officer.
- (5) Officers discharged after working for more than six months, continuously against leave vacancies.
- (6) Ex-servicemen invalidated out of service.
- (7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.
- (8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds etc.
- (d) The upper age limit shall also be relaxable to maximum of ten years for women candidate as prescribed in Madhya Pradesh Civil Service (Special provisions for appointment of Women) Rules, 1997;
- (e) The upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded superior caste partner of couple under the Inter Caste Marriage Incentive Programme of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Welfare Department;
- (f) The upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of widow, destitute and divorced woman candidate;
- (g) The upper age limit shall be relaxed upto a maximum of 2 years for those candidates who hold “Green Card” under the family planning programme;

- (h) The upper age limit shall be relaxable upto maximum period of 5 years in respect of Vikram Awarded candidate;
- (i) The upper age limit shall be relaxed upto 45 years in respect of candidate who are employees on any of the Madhya Pradesh State Corporation/Board;
- (j) The general upper age limit shall be relaxed in case of Voluntary Home-guards and Non-Commissioned Officers of Home-guards for a period of service rendered by them subject to the limit of 3 years but in no case their age should exceed 45 years;
- (k) The upper age limit shall be relaxable to the destitute candidates as per instructions issued by the State Government from time to time.

Note:—(1) Candidates, who are admitted to the examination/selection under the concessions mentioned in rules 8(1)(c) (i) and (ii) above, shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after examination / selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case their age limit shall not be relaxed.

- (2) Departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority to appear for the examination/selection.
- (3) The maximum age limit shall not be exceed than 45 years for all categories including all type of age relaxations, the base of maximum age limit shall be the General Administration Department circular No. 3-11/12/1/3, dated 03rd November 2012 and 20th November 2012.
- (2) **Educational Qualifications.**—The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as specified in Schedule III:

Provided that :—

- (a) In exceptional cases, the commission may in consultation with the Government on its recommendation treat as qualified any candidate, who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause has passed the examinations conducted by other institutions by such a standard for which, the Commission, considers the candidate eligible to appear in the selection/examination;
- (b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degree from Foreign Universities, being Universities not specifically recognized by Government, may also be considered for the selection of the discretion of the Commission.
- (3) **Fees.**—The Candidate must pay the fees prescribed by the Commission.

9. **Disqualifications.**—(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him appearing in the examination / selection.

(2) No candidate shall be eligible for appointment to the service/promotion, who is married before the minimum age fixed for marriage.

(3) No person shall be eligible for appointment to the service or post, who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th day of January, 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th day of January, 2001 in which two or more than two children are born.

(4) No candidate shall be eligible for appointment for a service or post who has been convicted for an offence against women:

Provided that where such cases are pending in a court against a Candidate, his case of appointment shall be kept pending till the final decision of criminal case.

(5) Male candidate who has more than one wives alive and female candidates who marries a male who has one wife alive will not be eligible for appointment.

10. Commission's decision about the eligibility of candidates shall be final.—The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of candidate for admission to selection shall be final and no candidate, to whom certificate of admission has not been issued by the commission, shall be allowed to appear in the examination/interview.

11. Direct Recruitment through Competitive Examination.—(1) The competitive examination and interviews for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the commission, determine from time to time.

(2) The examination shall be conducted by the commission in accordance with such orders, as the Government may from time to time issue in consultation with the commission.

(3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyaon, Anusuchit Jan Jatiyaon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and as per orders issued by the Government from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the select list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(6) There shall be reserved posts for disabled candidates in accordance with the directions issued by the General Administration Department. Reservation will be horizontal and compartment-wise.

(7) There shall be reserved post for ex-serviceman with the direction of the General Administration Department.

(8) If sufficient number of candidates are not available to fill the vacancies reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes then remaining vacancies shall not be filled by other category candidates without prior permission of the Government and these vacancies shall be kept reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for next selection.

(9) The candidates shall follow the provisions of Madhya Pradesh Civil Service (Conduct) Rules, 1965 during his whole service period.

12. List of candidates recommended by the Commission.—(1) The commission shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates, who have qualified by such standard as determined by the Commission and a list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, are declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied after such inquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

(4) The selection list shall be valid for the duration of one year from the date of issue by the Commission, which shall be extended for the period of six months with the consent of Commission.

13. Probation.—Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

14. Appointment by promotion.—(1) There shall be constituted a committee for making selection for promotion eligible candidates consisting of the members mentioned in Schedule- IV:

Provided that if the nominated member other than the member presiding the Departmental Promotion Committee in respect of the post to be filled up by the promotion do not represent category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, then one member belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the Departmental Promotion Committee and the number of members of Departmental Promotion Committee shall be extended to that limit.

(2) The Departmental Promotion Committee shall ordinarily meet at intervals not exceeding one year.

(3) Certification by the Appointing Authority.—The appointing authority shall endorse on the promotion order to be issued by him, a certificate to the effect that he was complied with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyaon, Anusuchit Jan Jatiyaon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Adhiniyam and the Rules made by the State Government and that he has full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Adhiniyam.

(4) Procedure for making promotions in the reserved vacancies shall be in accordance with the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

15. Conditions for eligibility for promotions.—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the committee shall consider the cases of all the person, who has completed such number of year of service (whether officiating or substantive) on the 1st day of January of that year on the post from which promotion is to be made on or any other post declared equivalent thereto by the Government as specified in column (3) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2):

Provided that any junior person shall not be given preference over the senior person only on the ground that he has completed prescribed service mentioned in this sub-rule.

(2) For the zone of consideration of promotion, of the candidate, the provisions the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002 shall apply.

16 Preparation of list of suitable candidate.—(1) The Committee shall prepare a list of suitable persons who has qualified the conditions laid down in rule 15, who are eligible for promotion. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of selection list.

(2) The criteria for preparation of select list shall be as per the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002.

(3) The name of persons included in the select list shall be arranged in the order of seniority in the service or post as specified in column (3) of Schedule-IV.

Explanation:—A person whose name is included in a select list shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision is proposed to supersede any member of the service, the committee shall record reasons for the proposed supersession.

17. Consultation with the Commission.—The recommendation of Departmental Promotion Committee presided over by the Chairmanship or a Member or Chairman of the Commission shall be deemed to be compliance of the requirement of consultation with the Commission under clause (3) of Article 320 of the Constitution of India and it shall not necessary to consult the commission separately.

18. Select list.—(1) The select list as finally approved by the Government will be the list for promotion for the members of the service from the posts given in column (2) of Schedule-IV to posts mentioned in column (3) of Schedule-IV.

(2) The select list shall ordinarily remain in force till it is either reviewed or revised as per the provisions of rule 16 but its legal validity shall not be extended beyond a period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the post of any person included in the select list, special review of the select list may be made at the instance of the Government and the commission may, if deems fit, may remove the name of such person from the select list.

19. Appointment to the Service from the Select List.—(1) Appointments of the persons included in the select list to the posts borne on the cadre of service shall follow the order of seniority in which the names of such persons appear in the select list.

(2) If it shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before the appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Government is such as to render his unsuitable for the appointment to the service.

20. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to Government, whose decision thereon shall be final.

21. Relaxation.—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such manner as may appear to him to be it to just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with any manner less favorable to the person than that provide in these rules.

22. Saving.—Nothing in these rules shall affect, reservations, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the instruction issued by the State Government from time to time in this regard.

23. Repeal.—The Madhya Pradesh Directorate of Handloom (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1986, corresponding to these rules, if any and inforce immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matter covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE-I

(See rule 5)

Classification of service scale of Pay and number of the posts included in the service

S.No.	Name of the post included in the service	No. of posts	Classification	Pay scale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Additional Director, Rural Industries	1	The Madhya Pradesh Directorate of Handloom (Gazetted) Service Class-I	Rs. 37400-67000+8700
2	Joint Director, Rural Industries (Handloom).	1	-do-	Rs. 15600-39100+7600
3	Joint Director, rural Industries (Technical).	1	-do-	Rs. 15600-39100+7600
4	Deputy Director, Rural Industries (Handloom)	5	-do-	Rs. 15600-39100+6600
5	Deputy Director, rural Industries (Technical)	5	-do-	Rs. 15600-39100+6600
6	Deputy Director (Finance)	1	-do-	Rs. 15600-39100+6600
7	Assistant Director, Rural Industries (Handloom).	29	The Madhya Pradesh Directorate of Handloom (Gazetted) Service Class – II	Rs. 15600-39100+5400
8	Assistant Director, Rural Industries (Technical).	25	-do-	Rs. 15600-39100+5400
9	Senior Personal Assistant	2	-do-	Rs. 9300-34800+4200

SCHEDULE-II
(See rule 6)
Method recruitment

Name of the Department	Name of Service/Post	Total No. of Posts	Percentage of the number of posts to be filled			Remarks
			By direct recruitment [see rule 6 (1)(a)]	By promotion of members of the service [see rule 6(1)(b)]	By temporary transfer of the persons of other service [see rule 6(1)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
The Directorate of Handloom	The Madhya Pradesh Directorate of Handloom (Gazetted) Service					
	Additional Director, Rural Industries	1	-	100%		
	Joint Director, Rural Industries (Handloom)	1	-	100%	-	-
	Joint Director, Rural Industries (Technical)	1	-	100%	-	-
	Deputy Director, Rural Industries (Handloom)	5	-	100%	-	-
	Deputy Director, Rural Industries (Technical)	5	-	100%	-	-
	Deputy Director, (Finance)	1	-	-	100%	Deputation from account service
	Assistant Director, Rural Industries (Handloom)	29	40%	60%	-	Out of total number of posts for promotion, one post shall be filled from clerical cadre (Superintend) and one post shall be filled from Steno cadre (Senior Personal Assistant) by promotion
	Assistant Director, Rural Industries (Technical)	25	50%	50%	-	
	Senior Personal Assistant.	2	-	100%	-	-

SCHEDULE-III

(See rule 8)

Minimum age and qualification for direct recruitment

Name of the Department (1)	Name service/post (2)	Minimum age limit (3)	Maximum age limit (4)	Prescribed educational qualification (5)	Remarks (6)
The Directorate of Handloom.	The Madhya Pradesh Directorate of Handloom (Gazetted) Service Class-II				
	Assistant Director, Rural Industries (Handloom)	21 years	40 years	1. A Bachelor Degree in Art/Science or Commerce from a recognized University. 2. Candidates having two years experience of the work relating to the handloom and other small scale industries and cooperation shall be preferred.	
	Assistant Director, Rural Industries (Technical)	21 years	40 years	1. 3 years Diploma/Degree in Textile/Weaving/Handloom Technology from recognized Institutions. 2. Candidates having experience of atleast two years in the work of textile industries shall be preferred. 3. Must have passed Higher Secondary (10+2) Examination of the Board of Secondary Education or any other examination equivalent thereto.	

SCHEDULE-IV
(See rule 13)

Name of Department	Name of service or post from which promotion is to be made	Name of service or post to which promotion is to be made	Period of experience of work on the lower post for being eligible for promotion	Name of members of the Departmental promotion committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
The Directorate of Handloom	The Madhya Pradesh Directorate of Handloom (Gazetted) Service			
	Joint Director, Rural Industries (Handloom)	Additional Director, Rural Industries	5 years	1. A Chairman of the Madhya Pradesh Public Service Commission or Any Member thereof Nominated by him—Chairman
	Joint Director, Rural Industries (Technical)			2. Additional, Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Government of Madhya Pradesh, Cottage and Rural Industries Department—Member
				3. Commissioner / Director Handloom Directorate—Member
				4. Nominated member belonging to Schedule Castes / Scheduled Tribes of equal rank—Member
	Deputy Director, Rural Industries (Handloom)	Joint Director, Rural Industries (Handloom)	5 years	—do—
	Deputy Director, Rural Industries (Technical)	Joint Director, Rural Industries (Technical)	5 years	—do—
	Assistant Director, Rural Industries (Handloom)	Deputy Director, Rural Industries (Handloom)	5 years	—do—
	Assistant Director, Rural Industries (Technical)	Deputy Director, Rural Industries (Technical)	5 years	—do—
	Rural Industries Extension Officer (Handloom)	Assistant Director, Rural Industries (Handloom)	5 years	—do—
	Rural Industries Extension Officer (Technical)	Assistant Director, Rural Industries (Technical)	5 years	—do—
	Superintendent	Assistant Director, Rural Industries (Handloom)	5 years	—do—
	Senior Personal Assistant	Assistant Director, Rural Industries (Handloom)	5 years	—do—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुसुम ठाकुर, उपसचिव.